जनेप प्राधिकरण देशाच्या पहिल्या प्रकारच्या बंदर आधारित कृषी प्रक्रिया सुविधेसाठी सवलतीच्या करारासह कृषी व्यापारात एक पाऊल पुढे टाकत आहे

जेएनपीएने मेसर्स ट्रायडेंट ॲग्रोकॉम एक्सपोर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि मेसर्स मॅन इन्फ्राकॉन्स्ट्रक्शन लिमिटेड (कन्सोर्टियम) यांच्याशी सवलत करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या

मुंबई, **12** मार्च **2025:** भारतातील सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरणाने मेसर्स ट्रायडेंट ॲग्रोकॉम एक्सपोर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि मेसर्स मॅन इन्फ्राकॉन्स्ट्रक्शन लिमिटेड (कंसोर्टियम) यांच्याशी जनेप प्राधिकरण येथे निर्यात-आयात सह देशांतर्गत कृषी वस्तू-आधारित प्रक्रिया आणि साठवण सुविधेच्या विकासासाठी सवलत करारावर स्वाक्षरी केली आहे. या प्रकल्पाचे मूल्य सुमारे 285 कोटी रुपये असून डीबीएफओटी (डिझाइन-बिल्ड-फायनान्स-ऑपरेट-ट्रान्सफर) मॉडेलवर सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (पीपीपी) तत्वावर हा प्रकल्प विकसित केला जाईल.

जनेप प्राधिकरणाचे अध्यक्ष श्री उन्मेष शरद वाघ, भा.रा.से म्हणाले की, या करारावर स्वाक्षरी करणे हे बंदर-आधारित औद्योगिक विकासाला चालना देण्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. अध्यक्षांनी अधोरेखित केले की सध्या कोणत्याही भारतीय बंदरात एकात्मिक कृषी-आधारित साठवण आणि प्रक्रिया सुविधा नसल्यामुळे, या प्रकल्पाची संकल्पना मांडण्यात आली. अशा प्रकारची ही पहिली सुविधा असून ही जागतिक पातळीवरील अशा सुविधांच्या तोडीसतोड सुविधा असणार आहे. या सुविधेमुळे कृषी-व्यापार बळकट होईल, व्यवसायाच्या नवीन संधी निर्माण होतील आणि भारताच्या कृषी निर्यातीला चालना मिळेल. लॉजिस्टिक्स आणि पुरवठा साखळी परिसंस्था बळकट करण्यासाठी जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा विकसित करण्याच्या जनेप प्राधिकरणाच्या वचनबद्धतेचा त्यांनी पुनरुच्चार केला.

जनेप प्राधिकरण येथे 27 एकर जमिनीवर प्रस्तावित अशा प्रकारची पहिली अत्याधुनिक सुविधा पर्यावरण मंजुरी (ईसी) आणि किनारी नियमन क्षेत्र (सीआरझेड) निर्बंधांपासून मुक्त आहे. अन्न सुरक्षा आणि व्यापार अनुपालन मानकांची पूर्तता करण्यासाठी कार्यक्षम प्रक्रिया, वर्गीकरण, पॅकिंग आणि प्रयोगशाळा चाचणी सुनिश्चित करण्यासाठी दरवर्षी अंदाजे 1.2 दशलक्ष टन कृषी वस्तू हाताळण्यासाठी याची रचना करण्यात आली आहे. ही सुविधा एकाच छताखाली शीतगृह, प्री-कूलिंग, गोठवलेली साठवणूक आणि कोरडी गोदामे यासह सर्वसमावेशक साठवण उपाय प्रदान करेल, ज्यामुळे कापणीनंतरचे नुकसान लक्षणीयरीत्या कमी होईल. यामुळे मांस, ताजी फळे आणि भाज्या, तसेच बासमती नसलेला तांदूळ, मका आणि सागरी उत्पादने आणि मसाले यासारख्या नाशवंत नसलेल्या वस्तूंसह विविध प्रकारच्या कृषी वस्तूंची आपूर्ती करेल. इष्टतम गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी, कापणीनंतरचे आणि वाहतुकीचे नुकसान कमी करण्यासाठी आणि कृषी व्यापाराची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी शेल्फ लाइफ वर्धन तंत्र, आधुनिक संरक्षण पद्धती आणि स्वयंचलित प्रक्रिया प्रणालींसह प्रगत तंत्रज्ञानाचा फायदा या सुविधेमुळे होईल. अखंडित लॉजिस्टिक्सला समर्थन देण्यासाठी, या सुविधेमध्ये निर्यात पॅकहाऊस, विस्तृत लोडिंग आणि अनलोडिंग झोन, प्रशासकीय सुविधा आणि शाश्वततेसाठी हरित जागा देखील समाविष्ट असतील. तसेच सुविधा आणि बंदराची एकूण कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी, सीमाशुल्क मंजुरी आणि अन्न चाचणी आणि प्रमाणीकरण यासह सुविधा या

सुविधेमध्ये प्रदान करण्याची कल्पना आहे. ही सुविधा देशांतर्गत आणि आयात केलेल्या कृषी वस्तूंसाठी स्थानिक वितरण केंद्र म्हणूनही काम करेल.

डिसेंबर 2024 मध्ये, जनेप प्राधिकरणाने मेसर्स ट्रायडेंट अॅग्रोकॉम एक्सपोर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि मेसर्स मॅन इन्फ्राकॉन्स्ट्रक्शन लिमिटेड (कन्सोर्टियम) यांना पुरस्कार पत्र (लेटर ऑफ अवॉर्ड) जारी केले. हा महत्त्वाचा उपक्रम कापणीनंतरचे नुकसान कमी करण्यात, अन्नसुरक्षेचे पालन सुनिश्चित करण्यात आणि कृषी निर्यातीला चालना देण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल अशी अपेक्षा आहे, ज्यामुळे भारताचा जागतिक कृषी व्यापार बळकट होईल. या सुविधेमुळे किनारी मार्गांद्वारे कृषी वस्तूंच्या वाहतुकीला देखील चालना मिळेल.

जनेप प्राधिकरणाबद्दल:

जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरण (जनेप प्राधिकरण) हे भारतातील प्रमुख कंटेनर हाताळणी बंदरांपैकी एक आहे. २६ मे १९८९ रोजी स्थापना झाल्यापासून, जनेप प्राधिकरण एक बल्क कार्गो टर्मिनलवरून देशातील प्रमुख कंटेनर बंदरात रूपांतरित झाले आहे.

सध्या, जनेप प्राधिकरण पाच कंटेनर टर्मिनल्स चालवते - एन एस एफ टी , एन एस आय सी टी, एन एस आय जी टी, बी एम सी टी आणि ए पी एम टी बंदरात सामान्य मालवाहतुकीसाठी उथळ पाण्याचा बर्थ देखील आहे. जनेप प्राधिकरण पोर्टवर उपस्थित असलेले लिक्विड कार्गो टर्मिनल बीपीसीएल-आयओसीएल कन्सोर्टियमद्वारे व्यवस्थापित केले जाते. याव्यतिरिक्त, नव्याने बांधलेला किनारी धक्का इतर भारतीय बंदरांना जोडतो आणि किनारपट्टीवरील कंटेनरची वाहतूक वाढवते.

277 हेक्टर जमिनीवर वसलेले, जनेप प्राधिकरण भारतातील निर्यात-केंद्रित उद्योगांना चालना देण्यासाठी, अत्याधुनिक पायाभूत सुविधांसह, काळजीपूर्वक डिझाइन केलेले बहुउत्पादक विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) देखील चालवते.

जनेप प्राधिकरण महाराष्ट्रातील वाढवण येथे सर्व हवामानात काम करण्यायोग्य, २० मीटर नैसर्गिक खोल, ग्रीनफिल्ड पोर्ट विकसित करत आहे. हे जागतिक स्तरावरील सर्वोत्कृष्ठ १० बंदरांमध्ये स्थान मिळवणार आहे आणि स्थापनेपासून १००% हरित बंदर असेल.

मीडिया चौकशीसाठी, कृपया संपर्क साधा:

जनेप प्राधिकरण:

अंबिका सिंग

सीनियर मॅनेजर (मार्केटिंग), जनेप प्राधिकरण

मोबाईल क्रमांक: +919920372677

ईमेल: ambikasingh@jnport.gov.in

जनेप प्राधिकरण ने देश की अपनी तरह की पहली पत्तन आधारित कृषि प्रसंस्करण सुविधा के लिए रियायत समझौते के साथ कृषि-व्यापार में एक कदम आगे बढ़ाया

जनेप प्राधिकरण ने मेसर्स ट्राइडेंट एग्रोकॉम एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स मैन इन्फ्राकंस्ट्रक्शन लिमिटेड (कंसोर्टियम) के साथ रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए

मुंबई, 12 मार्च, 2025: भारत के सर्वश्रेष्ठ पत्तन जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण ने जनेप प्राधिकरण में आयात-निर्यात सह घरेलू कृषि वस्तु-आधारित प्रसंस्करण और भंडारण सुविधा के विकास के लिए मेसर्स ट्राइडेंट एग्रोकॉम एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स मैन इंफ्राकंस्ट्रक्शन लिमिटेड (कंसोर्टियम) के साथ रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना का मूल्य लगभग 284 करोड़ रुपये है। इस परियोजना का मूल्य लगभग 285 करोड़ रुपये की लागत से इसे डिजाइन-निर्माण-वित्तपोषण-प्रचालन-ट्रांसफर (डीबीएफओटी) मॉडल पर सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड के तहत विकसित किया जाएगा।

जनेप प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री उन्मेष शरद वाघ भा.रा.से., ने कहा ने कहा कि इस समझौते पर हस्ताक्षर बंदरगाह आधारित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अध्यक्ष ने इस बात पर प्रकाश डाला कि चूंकि वर्तमान में किसी भी भारतीय बंदरगाह में कोई एकीकृत कृषि-आधारित भंडारण और प्रसंस्करण सुविधा नहीं है, इसलिए इस परियोजना की अवधारणा अपनी तरह की पहली सुविधा के रूप में और वैश्विक सुविधाओं के बराबर की गई है जो कृषि-व्यापार को मजबूत करेगी, नए व्यापार के अवसर पैदा करेगी और भारत के कृषि निर्यात को बढ़ावा देगी। उन्होंने लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति श्रृंखला पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के विकास के लिए जनेप प्राधिकरण की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

जनेप प्राधिकरण में 27 एकड़ भूमि पर प्रस्तावित अपनी तरह की पहली अत्याधुनिक सुविधा, पर्यावरण मंजूरी (ईसी) और तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) की बाधाओं से मुक्त है। यह सालाना लगभग 1.2 मिलियन टन कृषि वस्तुओं को संभालने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो खाद्य सुरक्षा और व्यापार अनुपालन मानकों को पूरा करने के लिए कुशल प्रसंस्करण, छंटाई, पैकिंग और प्रयोगशाला परीक्षण सुनिश्चित करता है। यह सुविधा एक ही छत के नीचे कोल्ड स्टोरेज, प्री-कूलिंग, फ्रोजन स्टोरेज और ड्राई वेयरहाउस सहित व्यापक भंडारण समाधान प्रदान करेगी, जिससे फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान में काफी कमी आएगी। यह मांस, ताजे फल और सब्जियों जैसी खराब होने वाली वस्तुओं के साथ-साथ गैर-बासमती चावल, मक्का और समुद्री उत्पादों और मसालों जैसी खराब न होने वाली वस्तुओं सहित कृषि वस्तुओं की एक विविध श्रृंखला को पूरा करेगा। यह सुविधा इष्टतम गुणवत्ता सुनिश्चित करने, फसल कटाई के बाद और पारगमन नुकसान को कम करने और कृषि व्यापार की दक्षता बढ़ाने के लिए शेल्फ जीवन

वृद्धि तकनीकों, आधुनिक संरक्षण विधियों और स्वचालित प्रसंस्करण प्रणालियों सहित उन्नत प्रौद्योगिकी का लाभ उठाएगी। निर्बाध लॉजिस्टिक्स के सहायता हेतु सुविधा में एक निर्यात पैकहाउस, व्यापक लोडिंग और अनलोडिंग ज़ोन, प्रशासनिक सुविधाएं और संधारणीयता के लिए हरित स्थान भी शामिल होंगे। सुविधा और पत्तन की समग्र दक्षता में सुधार करने के लिए, सीमा शुल्क मंजूरी और खाद्य परीक्षण और प्रमाणन सहित सुविधाओं को सुविधा में प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। यह सुविधा घरेलू और आयातित कृषि वस्तुओं के लिए एक स्थानीय वितरण केंद्र के रूप में भी काम करेगी।

दिसंबर 2024 में, जनेप प्राधिकरण ने मेसर्स ट्राइडेंट एग्रोकॉम एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स मैन इन्फ्राकंस्ट्रक्शन लिमिटेड (कंसोर्टियम) को पुरस्कार पत्र (लेटर ऑफ अवार्ड) जारी किया। इस ऐतिहासिक पहल से फसल कटाई के बाद के नुकसान को कम करने, खाद्य सुरक्षा अनुपालन सुनिश्चित करने और कृषि निर्यात को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है, जिससे भारत के वैश्विक कृषि व्यापार को मजबूती मिलेगी। यह सुविधा तटीय मार्गों के माध्यम से कृषि वस्तुओं की आवाजाही को भी बढ़ावा देगी।

जनेप प्राधिकरण के बारे में:

जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण (जनेप प्राधिकरण) भारत के प्रमुख कंटेनर- हैंडलिंग पत्तनों में से एक है। 26 मई 1989 को अपनी स्थापना के बाद से, जनेप प्राधिकरण ने एक बल्क कार्गो टर्मिनल से देश के प्रमुख कंटेनर पत्तन में परिवर्तन किया है।
वर्तमान में, जनेप प्राधिकरण पांच कंटेनर टर्मिनलों एनएसएफटी, एनएसआईसीटी, एनएसआईजीटी, बीएमसीटी और एपीएमटी का संचालन करता है। पत्तन में सामान्य कार्गो के लिए उथले पानी की बर्थ भी है। जनेप प्राधिकरण पत्तन पर मौजूद लिक्विड कार्गो टर्मिनल का प्रबंधन बीपीसीएल- आईओसीएल कंसोर्टियम द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त, नवनिर्मित तटीय बर्थ अन्य भारतीय पत्तनों को जोड़ता है और तटीय कंटेनरों के यातायात को बढ़ाने की सुविधा प्रदान करता है।
277 हेक्टेयर भूमि पर बसा जनेप प्राधिकरण भारत में निर्यातोन्मुखी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ एक सावधानीपूर्वक डिज़ाइन किया गया बहु-उत्पाद एसईजेड भी संचालित करता है।
जनेप प्राधिकरण, महाराष्ट्र के वाढवण में एक सभी मौसमों में सक्षम, गहरे ड्राबाव वाला, ग्रीनफील्ड पत्तन भी विकसित कर रहा है। यह वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 बंदरगाहों में शामिल होने की संभावना है, यह इसके स्थापना से ही 100% ग्रीन पोर्ट होगा।

मीडिया पूछताछ के लिए, कृपया संपर्क करें:

जनेप प्राधिकरणः

अंबिका सिंह वरिष्ठ प्रबंधक (विपणन), जनेप प्राधिकरण

मोबाइल नंबर: +919920372677

ईमेल: ambikasingh@jnport.gov.in

JNPA Takes a Step Forward in Agro-Trade with Concession Agreement for Nation's first-of-its-kind Port Led Agro Processing Facility

JNPA Signed the Concession Agreement with M/s Trident Agrocom Exports Private Limited and M/s Man Infraconstruction Limited (consortium)

Mumbai, March 12, 2025: Jawaharlal Nehru Port Authority (JNPA), India's Best Performing Port, has signed the Concession Agreement with SPV floated by M/s Trident Agrocom Exports Private Limited and M/s Man Infraconstruction Limited (Consortium) for the development of an Export-Import cum Domestic Agricultural Commodity-Based Processing and Storage Facility at JNPA. The project, valued at approximately Rs. 285 Crores, will be developed under the Public-Private Partnership (PPP) mode on a Design-Build-Finance-Operate-Transfer (DBFOT) model.

Shri Unmesh Sharad Wagh, IRS, Chairperson of JNPA, stated that the signing of this agreement marks a significant step in enhancing port-led industrial development. Chairman highlighted that since there is no integrated agro-based storage and processing facility in any Indian port currently, this project has been conceptualized as first of its kind facility and at par with global facilities which will strengthen agro-trade, create new business opportunities, and boost India's agricultural exports. He further reaffirmed JNPA's commitment to developing world-class infrastructure to strengthen the logistics and supply chain ecosystem.

The proposed first of its kind state-of-the-art facility, planned on 27 acres of land at JNPA, is free from Environmental Clearance (EC) and Coastal Regulation Zone (CRZ) constraints. It is designed to handle approximately 1.2 million tonnes of agricultural commodities annually, ensuring efficient processing, sorting, packing, and laboratory testing to meet food safety and trade compliance standards. The facility will offer comprehensive storage solutions, including cold storage, pre-cooling, frozen storage, and dry warehouses under one roof, which will significantly reduce post-harvest losses. It will cater to a diverse range of agricultural commodities, including perishable goods like meat, fresh fruits, and vegetables, as well as non-perishable items such as non-basmati rice, maize, and marine products and spices. The facility will leverage advances technology, including shelf life enhancement techniques, modern preservation methods, and automated processing systems to ensure optimal quality, reduce post harvest and transit losses and enhance the efficiency of agricultural trade. To support seamless logistics, the facility will also include an export packhouse, extensive loading and unloading zones, administrative facilities, and green spaces for sustainability. Also to improve the overall

efficiency of the facility and the Port, facilities including custom clearances and food testing and certification are envisaged to be provided in the facility. This facility will also act as a local distribution hub for the domestic and the import agricultural commodities.

In December 2024, JNPA issued the Letter of Award to M/s Trident Agrocom Exports Private Limited and M/s Man Infraconstruction Limited (Consortium). This landmark initiative is expected to play a pivotal role in reducing post-harvest losses, ensuring food safety compliance, and boosting agricultural exports, thereby strengthening India's global agricultural trade. This facility will also promote movement of agricultural commodities through coastal routes.

About JNPA:

The Jawaharlal Nehru Port Authority (JNPA) is one of the premier container-handling ports in India. Since its inception on May 26, 1989, JNPA has transformed from a bulk cargo terminal into the premier container port in the country.

Currently, JNPA operates five container terminals - NSFT, NSICT, NSIGT, BMCT and APMT. The Port also has a Shallow Water Berth for general cargo. A Liquid Cargo Terminal present at the JNPA Port is managed by the BPCL-IOCL consortium. Additionally, the newly constructed coastal berth links other Indian ports and facilitates enhancing the traffic of coastal containers.

Nestled across 277 hectares of land, JNPA also operates a meticulously designed multi-product SEZ, with state-of-the-art infrastructure, to boost export-oriented industries in India.

JNPA is also developing an all-weather, deep-draft, greenfield port at Vadhvan, in Maharashtra. It is poised to be among the top 10 ports globally and will be 100% green port since its inception.

For media enquiries, please contact:

Ambika Singh
Sr. Manager (Marketing), JNPA
Mob: +919920372677
E-mail: ambikasingh@jnport.gov.in